



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 66748

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 1648 सन् 2026

गौरव

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- गिरीश सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1 श्री गिरीश सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा श्री चंद्र शेखर सारन, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक गौरव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 919 सन् 2025, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद के अधीन विचाराधीन मुकदमे में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में पार्श्विक उद्देश्य से मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से 1129 ग्राम चरस बरामद होना आरोपित है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तलाशी एवं जब्ती से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, इस प्रकार स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 एवं 52-ए की अपेक्षाओं का उल्लंघन किया गया है। आवेदक 2.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और यह वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के दो मामलों का आपराधिक इतिहास है जो आवेदन में विधिवत् स्पष्ट किया गया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के कब्जे से 1129 ग्राम चरस बरामद होना कहा गया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 1129 ग्राम चरस बरामद होना आरोपित है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तलाशी एवं जब्ती से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, इस प्रकार स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 एवं 52-ए की अपेक्षाओं का उल्लंघन किया गया है। आवेदक 6.2.2026 से जेल में निरुद्ध है।

6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **गौरव** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए रु. 50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो जमानतदारों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लाएगा / उन्हें आतंकित नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप विरचन तथा

(iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अभिलिखित करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

30 मार्च, 2026

सुमैरा